भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2990

जिसका उत्तर 06 अगस्त, 2025 को दिया जाना है ।

15 श्रावण, 1947 (शक)

विकसित राज्य-विकसित भारत-2047

2990. श्रीमती डी. के. अरुणाः

श्री इटेला राजेंदरः

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य मोबाइल फोन, लैपटॉप और सर्वर निर्माण में प्रमुख परियोजनाओं के साथ प्रमुख इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण केंद्रों के रूप में तेजी से उभर रहे हैं और हैदराबाद एआई, बेंगलुरु एआई, चेन्नई एआई जैसे नए स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिकी क्लस्टर एक नई पहल हैं और भारतीय भाषाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में शामिल करने के तरीके पर एक बड़ा प्रभाव डालेंगे ताकि प्रौद्योगिकी और एआई के क्षेत्र के सार्वभौमीकरण के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने एआई मिशन स्थापित किए हैं जहां पूरा जोर सामान्य कंप्यूट सुविधा समाधान विकसित करने पर है जिसका उपयोग देश में किया जा सकता है और सरकार को उम्मीद है कि तेलुगु एआई, तमिल एआई जैसी पहलें तमिल और तेलुगु जैसी सबसे पुरानी भाषाओं के साथ एआई को एकीकृत करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाएंगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और इसमें कितनी धनराशि निवेश की गई है; और

(घ) 'विकसित राज्य-विकसित भारत -2047 के लिए निवेश स्थान के रूप में' हैदराबाद को विकसित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ग):** मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत पिछले 11 वर्षों में भारत में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। सरकार आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए घरेलू इलेक्ट्रॉनिकी इकोसिस्टम को सक्रिय रूप से सुदृढ़ कर रही है।

हाल के वर्षों में देश भर में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण इकाइयों द्वारा मूल्यवर्धन रूप से भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

सरकार ने रेडी बिल्ट फैक्ट्री (आरबीएफ) शेड सहित सामान्य सुविधाओं और प्रसुविधाओं के साथ-साथ विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) और संशोधित इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजनाओं को अधिसूचित किया है।

ईएमसी योजना के अंतर्गत, 15 राज्यों में 19 ग्रीनफील्ड ईएमसी और 3 सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्वीकृत किए गए हैं। ईएमसी 2.0 योजना के अंतर्गत, देश भर के 8 राज्यों में कुल 10 ईएमसी और 1 सीएफसी स्वीकृत किए गए हैं।

सरकार ने मार्च 2024 में इंडियाएआई मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य सात आधारभूत स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करके भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता हेतु वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करना है:

- **इंडियाएआई कंप्यूट क्षमता:** इसका उद्देश्य एमएसएमई और स्टार्टअप सहित सभी को किफायती कीमत पर उच्च स्तरीय कंप्यूट पावर (जीपीयू) प्रदान करना है।
- **इंडियाएआई फाउंडेशन मॉडल:** भारतीय डेटासेट और भाषाओं पर प्रशिक्षित भारत के अपने बड़े मल्टीमॉडल मॉडल (एलएमएम) विकसित करना। इसका उद्देश्य जनरेटिव एआई में संप्रभु क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है।
- **एआईकोश :** एआई मॉडलों के प्रशिक्षण हेतु बड़े डेटासेट विकसित करना। एआईकोश एक एकीकृत डेटा प्लेटफ़ॉर्म है जो सरकारी और गैर-सरकारी स्रोतों से डेटासेट को एकीकृत करता है।
- **इंडियाएआई एप्लीकेशन विकास पहल:** जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शासन और सीखने की अक्षमताओं के लिए सहायक प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में भारत की विशिष्ट चुनौतियों के लिए एआई एप्लीकेशनों का विकास करना।
- **इंडियाएआई फ्यूचरस्किल्स :** एआई क्षेत्र में स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी धारकों की संख्या बढ़ाकर भारत में एआई कुशल पेशेवरों का विकास करना। इसका उद्देश्य भारत भर के टियर 2 और टियर 3 शहरों में डेटा और एआई लैब स्थापित करना भी है।
- **इंडियाएआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग:** एआई स्टार्ट-अप को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- **सुरक्षित एवं विश्वसनीय एआई:** जिम्मेदारीपूर्ण एआई अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ शासन ढांचे के साथ नवाचार को संतुलित करना।

ये पहलें सामूहिक रूप से प्रारंभिक चरण की वित्तीय बाधाओं को कम करती हैं, उत्पाद विकास में तेजी लाती हैं और एआई स्टार्टअप के लिए वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाती हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार विभिन्न पहलों और एआई मॉडलों के माध्यम से भारतीय भाषाओं (संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल) को समर्थन दे रही है। सरकार ने भाषाई अवरोध की चुनौतियों को दूर करने और डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भाषिणी मिशन शुरू किया है ताकि नागरिक सभी भाषाओं में डिजिटल सेवाओं का उपयोग कर सकें।

भाषिणी एआई-संचालित भाषा मॉडल का उपयोग करता है। यह विभिन्न डोमेन में तमिल और तेलुगु सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं के अनुवाद में समर्थन करता है। इसके अलावा, इंडियाएआई मिशन ने सभी भारतीय भाषाओं (22) का समर्थन करने वाला एक आधारभूत मॉडल विकसित करने के लिए एक नवाचार चुनौती का आयोजन किया है और इसके परिणाम बाद में घोषित किए जाएँगे।

उपरोक्त के अलावा, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलें की हैं जो इस प्रकार हैं:

- बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई)
- आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई)
- इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी और ईएमसी 2.0) योजना
- इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टर्स के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीईसीएस)
- लागू कानूनों/नियमों के अधीन, इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण में 100% एफडीआई की अनुमति

ये सभी योजनाएँ अखिल भारतीय पहलें हैं और कोई भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश इन पहलों का लाभ उठा सकता है। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के स्थानों का चयन कंपनियाँ आपूर्ति श्रृंखला संपर्क, अवसंरचना समर्थन और राज्यों द्वारा प्रदान किए गए अन्य सुगमता प्रतिउपायों के आधार पर करती हैं।

****